

की स्थिति में चुनाव स्पष्ट हो

चुनावों के लिए मतदाताओं को सूचित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक ओर-ओर का ब्राडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है।

निर्वाचन करार जिसकी प्रतीति निर्वाचन आयुक्त को प्रेषित

मुख्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव पर रोक लगाई। यहाँ तक कार को फटकार लगाई। अब चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस बल का प्रयोग या घोषणा नहीं हो पाएगी।

ता केवल भारत में ही नहीं की है। इस प्रकार स्पष्ट है सरकार भारत में लोकतन्त्र

समस्या है अपने चुनाव शक्तिशाली बनाया जाए से सकता है।

विधान एक संवैधानिक प्रश्न है। ये बर्णन इस प्रकार है। प्रथमः यह है। मतदाता सूची में किसी जाति, लिंग के आधार पर और प्रत्येक राज के पर होगा। 61वें संशोधन से घटकर 18 वर्ष की

पर, विधि द्वारा, संसद के सदन के लिए सिद्ध है। के बारे में कानून निर्वाचन सम्बन्धी कानून

निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन सम्बन्धी अनुच्छेद 329 में है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिधीयन व अल्पसंख्यक सम्बन्धित मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। केवल संसद एवं विधानमण्डल सदस्यों के चुनाव को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	पदावधि
विश्वनाथ सैन	21 मार्च, 1950
ए. के. मुन्शरम	19 दिसम्बर, 1958
ए. के. शर्मा	20 दिसम्बर, 1958
ए. के. शर्मा	30 दिसम्बर, 1967
1 अक्टूबर, 1967	20 दिसम्बर, 1972
1 अक्टूबर, 1972	6 फरवरी, 1973
7 फरवरी, 1973	17 जून, 1977
18 जून, 1977	17 जून, 1982
18 जून, 1982	31 दिसम्बर, 1985
1 जनवरी, 1986	25 नवम्बर, 1990
26 नवम्बर, 1990	11 दिसम्बर, 1990
12 दिसम्बर, 1990	11 नवम्बर, 1996
12 दिसम्बर, 1996	13 जून, 2001
14 जून, 2001	7 फरवरी, 2004
8 फरवरी, 2004	15 मई, 2005
16 मई, 2005	29 जून, 2006
30 जून, 2006	20 अप्रैल, 2009
21 अप्रैल, 2009	29 जुलाई, 2010
30 जुलाई, 2010	10 जून, 2012
11 जून, 2012	जमी तक

भारत में चुनाव सम्बन्धी समस्याएँ

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है जिसमें 62 करोड़ से भी अधिक जनता है। यद्यपि भारत में निर्वाचन आयोग ने 15 लोकसभा चुनावों का प्रत्यक्षपूर्वक संचालन किया इसके बावजूद भारतीय लोकतन्त्र में अनेक चुनाव सम्बन्धी कमियाँ या समस्याएँ बनी हैं। जो इस प्रकार हैं

अप्रतिनिधित्वात्मक

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में एक मुख्य कमी है कि बहुमत मतदाता या 'वुल्ट पास्ट द पोस्ट' व्यवस्था में प्राप्त मतों की संख्या तथा जीती गई सीटों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अधिकतर चुनावों परिणाम यह दर्शाते हैं कि चुनाव में वोट का प्रतिशत एवं जीती गई सीटों की संख्या में असन्तुलन होता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुमत प्राप्त दल को 50% मत नहीं प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में 50% से कम मत प्राप्त व्यक्ति ही विजयी घोषित हो जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक है तो यह प्रतिशत बहुत कम हो सकता है।

दलों एवं प्रत्याशियों की बहुलता

वर्तमान में देश में लगभग 700 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। दलों की बहुलता न सिर्फ मतदाताओं में भ्रम पैदा करती है बल्कि चुनाव में उम्मीदवारों को अत्यधिक संख्या प्रशासनिक समस्याएँ भी उत्पन्न करती है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों की अधिक संख्या इस समस्या को और बढ़ा देती है।

ऐसे सिद्धान्तविहीन व्यक्ति आधारित दल एवं स्वतन्त्र उम्मीदवार चुनाव के बद के परिदृश्य में अवसरवादी गठबन्धन एवं अस्थिर सरकार को समस्या उत्पन्न करते हैं।

बढ़ते खर्च एवं धन का प्रभाव

भारत में चुनाव बढ़ते चले तथा इसे संगठन करने वाले, दलों के लिए यह खर्चीली व्यवस्था है। 13वें आम चुनाव में सरकार की सिर्फ सरकारी चुनाव में ₹ 850 करोड़ खर्च करने पड़े। अतिथर सरकारों के कारण होने वाली धार-धार चुनावों में इस समस्या को और गम्भीर बना दिया।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो कानून द्वारा लोकसभा चुनाव में 25 लाख, विधानसभा चुनावों में 10-15 लाख सीमा निर्धारित है, परन्तु कानून प्रभावी न होने के कारण एक उम्मीदवार का खर्च करोड़ पर पहुँच जाता है। यह बढ़ता खर्च अनैतिकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में ईमानदार व कुशल उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ खर्च करने वाले उम्मीदवार को सभा प्रण होती है जो वह चुनाव में खर्च किए गए धन की उतारी सरकारी यहाँतरी के दुरुपयोग, रिश्वत एवं घोटालों से करता है।

चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग

समाजवादी दल चुनावों में निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग करता है। वह अपने कृपाचार अधिकारियों को नियुक्त कर मतदाता सूची में अवैधानिक हेर-फेर, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था में हेर-फेर आदि करता है।

हिंसा एवं बाहुबल

चुनावों में जोत की ही अन्तिम सत्य मानने वाले प्रत्याशी धन शक्ति के साथ-साथ बाहुबल की शक्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकिचाते। बाहुबल का अर्थ अपराधियों की सहायता लेना, हिंसा एवं बल का प्रयोग करना मतदाताओं को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना। यह घटनाएँ चुनावों के साथ सामान्य सी बन गई हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

चुनाव में बाहुबल की शक्ति के प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि स्थानीय बाहुबली एवं अपराधियों का, जिनका प्रयोग नेता माध्यम रूप में करते थे, अब वे सीधा राजनीति में भाग लेने लगे हैं। पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री वी. कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1996 के लोकसभा उम्मीदवारों का उदाह नमूने में बताया कि 13,952 उम्मीदवारों में से 1500 अपराधिक पुष्टभूमि हैं। जनवरी, 2001 को निर्वाचन आयोग को स्वर्ण जयन्ती के अवसर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भी अपने भाषण में कहा कि संसद व विधान में अनेक नेता अपराधिक पुष्टभूमि के हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान से जब अपराधियों को टिकट देने के बारे में पूछा ग उनोंने स्पष्ट कहा कि हम 'जेर के सामने बकरी' को नहीं उतार सकते

चुनावों में जाति एवं धर्म की भूमिका

दत्ता आयोग, रघुवीर दयाल आयोग आदि ने स्पष्ट कहा कि ने प्राप्ति के लिए सम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं। गुजरात दंगे (2001) स्पष्ट किया कि नेता राजनीति में धर्म का कार्ड लेते हैं। जाति का दौरान प्रयोग तो एक सामान्य घटना है। उपरोक्त समस्याओं ने भारत सुधारों को आवश्यक बना दिया है।

भारत में चुनाव सुधार सम्बन्धी प्रयास

भारत में 'स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष' चुनाव कराने और लोकतन्त्र रखने के लिए एक ओर विभिन्न समितियों का गठन किया गया

संगठन एवं नियुक्ति

अनुच्छेद 324(2) में उपबन्ध है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा। पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, परन्तु वर्ष 1993 से निर्वाचन आयोग तीन-सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं और निर्णय बहुमत से किए जाते हैं।

पदावधि व हटाने की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ओं भी पहले हो, पद धारण करेंगे। परन्तु

- वह राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है।
- अन्य चुनाव आयुक्तों व प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ वृहद हैं, आम चुनावों के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्तियों के तीन क्षेत्र हैं

- प्रशासनिक, • परामर्शदात्री • अर्द्ध-न्यायिक।
- चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन है
 - संसद राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, निवृत्तन एवं निर्देशन करना।
 - मतदाता सूचियों तैयार करना।
 - विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।
 - राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव-चिह्न प्रदान करना।
 - चुनाव क्षेत्रों के परिमार्जन या सीमांकन में परिमार्जन आयोग को सहायता करना।
 - अर्द्ध-न्यायिक कार्य, जैसे-अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है तथा अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्यपाल राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है।
 - राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
 - राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रसार की सुविधाएँ दिलवाना।
 - उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जाँच करना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संशोधन 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देते हैं।
 - मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।
 - राष्ट्रपति को प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श देना।
 - सरकार को अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना।
 - चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देना।
 - राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की जाँच की तिथि, चुनाव संपर्क के नाम वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है।

- चुनाव आयोग, हिंसा, बूथ कैम्पेयरिंग आदि की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है।

चुनाव आयोग की भूमिका

निर्वाचन आयोग ने भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वर्ष 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कार्यवाही सरकार को वास्तविक या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोकता। इसके परन्तु का आकर को साम्प्रदायिक भाषण देने के कारण छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर चुनाव के दौरान धर्म, जाति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए एक ओर पोस्टो पहचान-पत्र लागू किए तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लागू किया।

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष निर्वाचन कराए जिसकी प्रशंसा विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी की। इसी कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के हस्तान्तरण पर रोक लगाई। यहाँ तक राजस्थान में धानाध्यक्ष के हस्तान्तरण करने पर सरकार को फटकार लगाई। वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश व बिहार विधानसभा के चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय पर्यवेक्षकों व केन्द्रीय पुलिस बल का प्रयोग किया, जिसके कारण इन राज्यों में बूथ कैम्पेयरिंग व चॉपली नहीं हो पाई और जनता ने निह्र मतदान किया।

चुनाव आयोग ने निष्पक्ष व क्रियाशील भूमिका केवल भारत में ही नहीं अपितु भूटान, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी अदा की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाकर भारत में लोकतन्त्र को रक्षा की।

परन्तु निर्वाचन आयोग के पास सबसे बड़ी [सम्स्या] है अपनी चुनाव मशीनरी न होना। यदि चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए तो भारत विश्व के लिए 'आदर्श लोकतन्त्र' का रूप ले सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक संवैधानिक प्रावधान हैं। निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है

- अनुच्छेद 324 में 'निर्वाचन आयोग' सम्बन्धी उपबन्ध है।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 326 में उपबन्ध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य को विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। 61वें संशोधन अधिनियम (1988) में वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई।
- अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन के लिए निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाएगी।
- अनुच्छेद 328 यदि संसद राज्य विधानमण्डल के बारे में कानून नहीं बनाती है तो राज्य विधानमण्डल अपने सदन के निर्वाचन सम्बन्धी कानून बना सकती है।

चुनाव प्रणाली और हित (Electoral System and Interest G

चुनाव प्रणाली (Electoral System)

किसी भी लोकतान्त्रिक राष्ट्र में निर्वाचन एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। चुनाव ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी हद तक उन पर नियन्त्रण भी रखती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इन्दिरा गाँधी बनाम राजनारायण (1975) बाद में 'स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव' को संविधान के आधारभूत ढाँचे का आवश्यक तत्त्व बताया। भारतीय संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान किए हैं।

भाग -15 (निर्वाचन)

- अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
- अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।
- अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
- अनुच्छेद 327 विधानमण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की उस विधानमण्डल की शक्ति।
- अनुच्छेद 329 निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।
- अनुच्छेद 329(A) (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबन्ध) 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 36 द्वारा निरसित

चुनाव आयोग

भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वायत्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार संसद और राज्य विधानमण्डल के निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार करने का और निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा।

(D) 4 और 1
निम्नलिखित को
केस
D
2
1
नों को सही कालक्रम
केस
10. (d)
20. (c)
30. (d)
40. (c)
50. (a)
60. (d)
70. (a)
80. (a)
90. (d)
100. (b)
110. (c)
120. (b)

देश में
एवं उन
करने
तहत
के रूप
324 में
चुनावों
पदों के
निर्देशन
आयोग

सामान्य विद्योत संघ, इनमें महत्वपूर्ण रहे हैं। इन सबके केन्द्र में अमीर और मध्यम वर्ग के कृषकों का असन्तोष है।

उद्देश्य समूह

उद्देश्य समूहों का मुख्य उद्देश्य सामान्य सामाजिक विषयों; जैसे—पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा, बुन्दू-दण्ड को समाप्त, पुनर्जागरण सुधारों का प्रारम्भ, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना, इत्यादि को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे समूहों को, जो इस बात पर ध्यान देने के लिए सामूहिक सामाजिक हित को आगे बढ़ाते हैं, न कि चुने हुए समूहों के हित को, जनहित समूह भी कहते हैं। ये समूह सुसंगठित भी हो सकते हैं और नहीं भी। उनकी सफलता संगठन से अधिक जनता और जन संचार माध्यमों के सहयोग पर निर्भर करती है। अपने बड़े बाँधों के निर्माण का विरोध करने वाले, झुग्गियाँ हटाने, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, दहेज इत्यादि का विरोध करने वाले समूहों के विषय में अवश्य सुना होगा।

वही समूह उद्देश्य समूह है, जो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं।

संस्थागत समूह

संस्थागत समूह ऐसे समूह हैं जो सरकार के भीतर हैं और सरकारी एजेंसियों के द्वारा दबाव अथवा प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अफसरशाही और सेना संस्थागत समूह के स्पष्ट उदाहरण हैं। उन समूहों के भीतर एक आईपीएस, आईपीएस और आईएफएस लॉबी के बारे में सुनते हैं। इस प्रकार मन में प्रायः थल सेना, वायु सेना और नौ सेना इत्यादि कुछ विषयों पर प्राथमिकता के लिए दबाव की बातें सुनाई पड़ती हैं। ऐसे समूह अलोकतांत्रिक प्रणाली में विशेषतः महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ स्वायत्त समूहों को प्रायः दबा दिया जाता है। लेकिन ये लोकतन्त्र में अभिजनो के बीच प्रतियोगिता के रूप में सक्रिय

रहते हैं। भारत में भी अपनी गतिविधियों के माध्यम से वे कानूनी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी गतिविधियाँ जनता में दिखाई नहीं देती। वे अपनी पसन्द के क्षेत्र में संसाधनों के निर्धारण अथवा अपनी प्राथमिकता भूमिका के क्षेत्र में नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने उद्देश्य का समर्थन करने वाले समूहों की सहायता भी करते हैं।

तदर्थ समूह

अन्ततः कुछ ऐसे समूह हैं, जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी समय सरकार पर दबाव डालने के लिए अस्तित्व में आते हैं। इसलिए वे उद्देश्य पूरा होने तक ही सक्रिय अथवा संगठित रहते हैं। ऐसे समूहों में एक शहर में रेल सुविधा चाहने वाले, किसी पुस्तक या गतिविधि पर पाबन्दी चाहने वाले, कोई स्कूल, कॉलेज अथवा अस्पताल इत्यादि खुलवाने जैसे समूह सम्मिलित होते हैं। ऐसे समूह कुछ समय के लिए बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इनमें से कुछ चर्चे भी रह सकते हैं और अपनी गतिविधियों का विस्तार उद्देश्य के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति के दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, परन्तु इनकी अधिक सक्रियता के लिए निम्न सुधार आवश्यक हैं

- दबाव समूह में वचनबद्धता और एकता स्थापित की जाए।
 - दबाव समूह संवैधानिक साधनों तथा प्रचार, प्रेस और लॉबीइंग का प्रयोग करें।
 - सामुदायिक दबाव समूह की सक्रियता को बढ़ाया जाए।
 - दबाव समूह नीति-निर्माण व राष्ट्र-निर्माण के लिए कार्य करें।
- इन सुधारों के साथ ही भारतीय लोकतन्त्र में दबाव समूह प्रभावशाली भूमिका अदा कर पाएँगे।

जनमत (Public Opinion)

जनमत की परिभाषा

नौरिस गिसबर्ग के अनुसार "जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्त्व का निर्माण होता है, वह लोकमत होता है"। इस प्रकार गिसबर्ग जनमत को जनता की इच्छा के रूप में परिभाषित करता है। किन्तु गिसबर्ग के शब्दों में "जनमत जनसाधारण समय विशेष पर किसी विषय पर जो विचार रखते हैं वही जनमत है।"

जनमत-निर्माण/जनमत की अभिव्यक्ति के साधन

भारत में जनमत-निर्माण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं

- समाचार-पत्र
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- शिक्षण संस्थाएँ
- विधानमण्डल
- राजनीतिक दल एवं दबाव समूह
- सांस्कृतिक व धार्मिक समुदाय
- मानवीय तत्त्व

जनमत का तात्पर्य सार्वजनिक विषयों पर जनसाधारण का मत है। लावेल ने जनमत के सम्बन्ध में तीन तत्त्व बताए हैं

- जनमत जनता का मत होता है।

- जनमत स्याई विचार होता है।
- सार्वजनिक हित से सम्बन्धित होता है।

लोकतन्त्र में जनमत का महत्त्व

लोकतन्त्र को जनमत की प्रमुख आधारशिला माना जाता है। लोकतन्त्र में जनमत को महत्त्व इस प्रकार है

- जनमत लोकतन्त्र में शासन का पथ-प्रदर्शन करता है।
- जनमत सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है।
- वह नागरिकों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखता है।
- शासन के उत्साह को बढ़ाने का कार्य करता है
- स्वार्थी राजनेताओं व संस्थाओं पर नियन्त्रण करता है।

जनमत की सीमाएँ

जनमत के निर्माण में अनेक बाधाएँ होती हैं, भारतीय जनमत के निर्माण में निम्नलिखित बाधाएँ हैं

- शिक्षा का अभाव
- सरकारी नीतियों में जनता को अरुचि
- मीडिया की स्वतन्त्रता का अभाव
- जनता में असमानता
- जनता व सरकार के लक्ष्यों में समानता का अभाव।

अथवा वर्ग के आधार पर न होकर जन्म पर आधारित होती है। इन समूहों को और आगे दो भागों में बाँटा जा सकता है एक वे जो मूलतः सामुदायिक सेवा से सम्बद्ध हैं और दूसरे वे जो राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतियोगिता में सामुदायिक अथवा सामाजिक सक्रियता का प्रयोग करते हैं।

पहले प्रकार में हम वीएचई शिक्षण संस्थाएँ, रामकृष्ण मिशन, मुख्य खालसा टोबान सिंह सभाएँ, मुस्लिम शिक्षण ट्रस्ट, बकम मीलबी संस्था, अल-अमीन शिक्षण संस्था, एंग्लो इण्डियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जैन सेवा संघ और ऐसी अनेक संस्थाओं का उल्लेख कर सकते हैं, जो अपने-अपने समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संलग्न हैं। इस उद्देश्य के लिए वह सरकार के आर्थिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता को अपेक्षा करते हैं और इसके लिए दूसरे समुदायों के प्रति किसी पूर्वाह्व तथा जातीय या सामुदायिक विवाद प्रोत्साहित किए बिना सरकार का दबाव झालते हैं।

दूसरे प्रकार के पहचान समूह वे हैं जो विशेष स्तर, श्रेष्ठता अथवा दूसरों की तुलना में अपने समुदाय के लिए प्राथमिकता का दावा करने में संलग्न हैं। मुसलमानों में जमायात-ए-इस्लामी, हिन्दुओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद और सिखों में अखिल भारतीय सिख छात्र परिषद ऐसे ही समूह हैं। ये समूह न केवल अपने समुदायों के हित के लिए कार्यरत हैं अपितु अपनी मूल्य पद्धति के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया के स्थानान्तरण के लिए भी कार्य करते हैं। भाषा के विकास को अपसर करने वाली कई भाषायी संस्थाएँ भी हैं।

सामुदायिक अथवा व्यावसायिक समूह

सामुदायिक अथवा व्यावसायिक समूह वे समूह हैं, जो संयुक्त व्यावसायिक हितों के लिए एकत्रित हुए व्यक्तियों द्वारा गठित किए गए हैं। उन्हें कभी-कभी संरक्षक और कार्यात्मक समूह भी कहा जाता है। मजदूर संघ, व्यापार संस्थाएँ और मजदूर संस्थाएँ, व्यावसायिक संगठन आदि इस प्रकार के समूहों के प्रमुख उदाहरण हैं। उनका महत्वपूर्ण विशेषता इस तथ्य में है कि वे समाज के एक वर्ग, जैसे—मजदूर, मालिक, उपभोक्ता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह भी कहा जाता है कि ये समूह आधुनिक आर्थिक और व्यावसायिक हितों पर आधारित हैं। इनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्थाएँ उद्योग और व्यापार समूह, मजदूर संघ और कृषक तथा खेती हर मजदूरों की संस्थाएँ हैं।

व्यापार समूह

नीतियों को प्रभावित करने तथा हितों को रक्षा करने की दृष्टि से किसी भी समाज में व्यापार और उद्योग सबसे बड़ा और सक्रिय वर्ग है। भारत में उन्होंने स्वयं को औपनिवेशिक काल में ही संगठन करना प्रारम्भ कर दिया था। उस समय जब वे स्वयं को कांग्रेसी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आन्दोलन की विरोधी नीति से अलग-अलग रहने के पक्षधर थे, तब भी उन्होंने कांग्रेस की रचनात्मक गतिविधियों और स्वतन्त्रता के कार्यक्रमों में कई प्रकार से सहयोग दिया। स्वतन्त्र भारत में व्यापार और उद्योगों को विकास की नीतियों और योजनाओं के सन्दर्भ में कार्य करना था।

इन नीतियों के अन्तर्गत उनके पास विकास की सम्भावनाएँ भी थीं और उस समय अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेन्स और नियन्त्रण के माध्यम से प्रतिबन्धों की आशंकाएँ भी थीं। इसलिए उन्होंने सरकार पर अपने हित के लिए दबाव डालने हेतु संगठित होने की अति-आवश्यकता अनुभव की। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की व्यापार और वाणिज्यिक संस्थाएँ उभरीं।

मजदूर संघ

मजदूर एक महत्वपूर्ण संगठित वर्ग के रूप में लगभग पूरे विश्व में उभरीं। इस सन्दर्भ में मार्क्सवादी और समाजवादी दलों के उदय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तीव्र औद्योगिकरण की नीति, उद्योग बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना और विकास, लाखों लोगों को नौकरों में रखना, सरकार का समाजवादी रूप और साम्यवादी दलों का पुनर्गठन आदि लेने का निर्णय, इन सबसे मिलकर मजदूर संघ आन्दोलन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराईं हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने मजदूर संघ, महासंघ, जैसे—इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ़ेडरेशन (आईएनटीयूसी), ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ़ेडरेशन (एजाईटीसी), मजदूर सभा (एचएमएस), सेक्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) इत्यादि प्रयोजित करने प्रारम्भ कर दिए हैं।

भारत में लगभग विगत पाँच दशकों से मजदूर संघ आन्दोलन ने धार्मिक सामाजिक प्रणाली में निश्चित रूप से अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। फलस्वरूप नीति निर्णय निर्धारण स्तर पर कार्यरत श्रमिक वर्ग दबाव झालने के सक्षम रहा है और इसकी शक्ति को सभी राजनीतिक दल और सरकारें नज़र पहचानती हैं, यद्यपि आर्थिक विवशता और बाढ़ नेतृत्व के दायरे में, ये अपनी माँगों के लिए अत्यधिक मुखर और तरीकों में तृप्त भी हो सकते हैं। कुछ श्रेष्ठों में उद्योगों की सघनता के कारण ये राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण मत-शक्ति उपलब्ध करा सकते हैं।

इस कारण, संगठित मजदूर वर्ग, अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में कुछ सफलताएँ प्राप्त करने में सक्षम रहा है। मजदूर संघों ने अपनी गतिविधियों द्वारा मजदूरों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने करने में भी काफी सहायता की है। अब भी समाज में मजदूर संघ सर्वश्रेष्ठ सुसंगठित समूह हैं। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया मजदूरों के समग्र एक गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इसलिए नई आर्थिक व्यवस्था में मजदूर संघों को अपनी भूमिका के लिए स्वयं का पुनर्नीकरण करना होगा।

किसान और कृषक संगठन

यह सुविदित है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है और भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही है। स्वतन्त्रता के समय सरकार के लिए एक और कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था तो दूसरी ओर भूमि-सुधार लागू करना। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने में तथा हरित-क्रान्ति, सीमित भूमि-सुधार और चुनावों राजनीति में ग्रामीण लोगों को सक्रिय करने जैसी नीतियों और कार्यक्रमों ने ग्रामीण लोगों में जागरूकता और चेतना पैदा की तथा भिन्न-भिन्न हित वाले नए समूह बने। तत्पश्चात् ये हितों के रक्षार्थ एवं संघर्ष हेतु संगठित समूहों एवं आन्दोलनों के रूप में उभरीं। कई पर्यवेक्षक इन समूहों को प्रचलित शब्दावली में 'किसान समूह' या कृषि आन्दोलन भी कहते हैं। वास्तविकता यह है कि किसानों के समुच्चय हित नहीं होते। वे भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न होते हैं। वृहद् दृष्टि से हम इनको दो समूहों—खेतिहर समूह तथा कृषक समूह में बाँट सकते हैं।

खेतिहर संस्थाएँ

पिछले कई वर्षों से खेतिहर आन्दोलन समाचारों में रहे हैं। 1970 के दशक के अन्तिम वर्षों से कृषक स्वयं को संस्थाओं से संगठित करते रहे हैं और कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमतें, बिजली दरों में कटौती, कृषि निवेश के लिए सस्ती दरों पर ऋण तथा खाद पर सब्सिडी, इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम भारत विकास यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, कर्नाटक में कर्नाटक

भारतीय राजनीति में दबाव समूह

दबाव समूह अनेक व्यक्तियों का संगठन है, जिनके हित समान होते हैं, दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं।

दबाव समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। अतः हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह पाए जाते हैं, पुराने लोकतान्त्रिक प्रणाली में दबाव समूहों की विशेष भूमिका होती है। उल्लेखनीय है कि अध्येक्ष्यतात्मक शासन प्रणाली में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अन्तः

राजनीतिक दल व दबाव समूह में अन्तर निम्नलिखित हैं

- राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह नहीं।
- राजनीतिक दल औपचारिक संगठन हैं, जबकि दबाव समूह औपचारिक/अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हैं।
- राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक देशों में पाए जाते हैं, जबकि दबाव समूह सभी प्रकार की शासन प्रणाली में पाए जाते हैं।
- एक व्यक्ति एक ही दल का सदस्य होता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य होता है।
- राजनीतिक दलों में विचारधारा का तत्त्व पया जाता है, जबकि दबाव समूह में विचारधारा का तत्त्व नहीं पाया जाता है।
- राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करते हैं, जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार का निर्माण नहीं करते हैं।
- राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं जबकि दबाव समूह संवैधानिक के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं।

भारतीय राजनीति में दबाव समूह की प्रकृति

प्रो. माथरन वीनर ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स ऑफ स्कारसिटी' में तथा स्टेनली कोचनीक ने अपनी पुस्तक 'बिजनेस एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया' में भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है।

इन अध्ययनों के आधार पर दबाव समूह की प्रकृति इस प्रकार स्पष्ट होती है

- भारत के सभी दबाव समूहों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वे राजनीतिक दलों के सहायक अंग बनकर रह गए हैं और उन्हीं के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं।
- पारिवारिक और जातीय दबाव समूह भारत में अधिक क्रियाशील हैं।
- दबाव समूह का विकास स्वयं राजनीतिक दलों द्वारा होता है।
- दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा सरकार को प्रभावित करते हैं।
- दबाव गुट भारत में आन्दोलनकारी नीति दबाव के लिए अधिक अपनते हैं।
- दबाव समूहों में आपसी एकता का अभाव है।
- दबाव समूहों में राजनीतिक व सैद्धान्तिक वचनबद्धता का अभाव है।

दबाव समूह की प्रमुख तकनीकें या कार्यविधियाँ

भारत के दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक कार्यविधियों का प्रयोग करते हैं। यथा

मनोरंजन और प्रलोभन

विधायकों और उच्च सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह (मुख्यतः व्यावसायिक दबाव समूह) दावतों, भेंट, रिस्वन आदि का सहारा लेते हैं। इनके अतिरिक्त विदेश-यात्रा का प्रलोभन, सेवानिवृत्ति के बाद निजी संस्थाओं में उच्च पद, रिश्तेदारों को अच्छी नौकरियाँ आदि का प्रलोभन दिया जाता है।

व्यापक प्रचार

जनमत और शासन को प्रभावित करने के लिए पत्र-पत्रिकाएँ, भाषण, सभाएँ, सम्मेलन आदि की सहायता ली जाती है।

निर्वाचन के समय सहायता

दबाव समूहों के अपने विशेष प्रकार के हित और दर्शन होते हैं, चुनाव के समय ये समूह ऐसे प्रत्याशियों का चयन कराते हैं, जो उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दें। ऐसे प्रत्याशियों या उनके दल को समर्थन के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

लॉबीइंग

लॉबीइंग का अर्थ है—विधायकों से मिलकर अपने हितों में कानून का निर्माण करवाना। भारत में भी अब लॉबीइंग का प्रयोग दबाव समूह करने लगे हैं।

आन्दोलन और बल प्रयोग

जब प्रार्थना और अनुरोध के साधन असफल हो जाते हैं, प्रष्ट साधनों द्वारा सफलता नहीं मिलती और न्यायालय भी सहायक नहीं होते, तो दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हड़ताल, बन्द, धरना, प्रदर्शन, भूख-हड़ताल, घेराव और कभी-कभी आत्म-दाह तक का भी आश्रय लेते हैं।

न्यायपालिका की शरण

कभी-कभी दबाव गुट ऐसे कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को रद्द करने के लिए जो उनके हितों के विरुद्ध होते हैं, न्यायालय की शरण लेते हैं। अतिरिक्त, ज्ञापन देना, शिष्टमण्डल भेजना, समारोह आयोजित करना शामिल हैं। वस्तुतः भारत में साम्प्रदायिक व जातीय दबाव समूह अधिक हैं, जो आन्दोलन और बल प्रयोग का अधिक सहारा लेते हैं। विधायन द्वारा आरक्षण की माँग के लिए चलाए गए आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

भारत में दबाव समूह के प्रकार

सामाजिक अथवा पहचान आधारित दबाव समूह

औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य मूल्यों और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रतिकार करने के लिए, नए व्यवसायों तथा सरकारी नौकरियों में भाग की माँग करने तथा संख्या आधारित राजनीति में सामाजिक तथा जातीय हितों की रक्षा के लिए धर्म, जाति, भाषा, जातीयता और क्षेत्रीयता, इन सामुदायिक हितों पर आधारित कई समूह सामने आए। कुछ विधायकों प्रशासन ने स्वयं ऐसे समूहों के गठन को राष्ट्रीय आन्दोलन की कुछ प्रतिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतन्त्रता उपरान्त लगे व्यवस्था और सीमित संसाधनों के लिए प्रतियोगिता के सन्दर्भ में ऐसे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

सामाजिक अथवा पहचान आधारित समूहों की मुख्य विशेषता सामाजिक ताने-बाने से बुने जाते हैं। इस अर्थ में उनकी सदस्यता